नईदुनिया

पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र में हंगामे के बीच चार विधेयक पारित, पीईसीए पर नारेबाजी

इस्लामाबाद

मुल्क के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों के हंगामे के बीच संघीय सरकार ने संसद के संयुक्त सत्र में चार विधेयकों को पारित कर दिया। पीटीआई नेता हाथों में तख्तियां लेकर सदन में दाखिल हुए और पीईसीए अधिनियम अस्वीकार्य और पत्रकारों का उत्पीड़न अस्वीकार्य जैसे नारे लगाए। पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) 2016 में गुरुवार को किए गए संशोधनों का विरोध करते हुए सत्र को कवर करते समय बाजू पर काली पट्टियां बांधी। विपक्षी नेता उमर अयूब के औचित्य के प्रश्न पर बोलने के अनुरोध को नेशनल असेंबली अध्यक्ष अयाज सादिक ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए और विधायी एजेंडे की प्रतियां फाड़ दीं। हंगामे के बावजूद सरकार चार विधेयकों को पारित करने में सफल रही। यह विधेयक हैं- व्यापार संगठन (संशोधन) विधेयक 2021, आयात और निर्यात नियामक (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2024, राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान विधेयक 2024। हालांकि राष्ट्रीय मानव विकास आयोग (संशोधन) विधेयक 2023, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संघीय उर्दू विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023 पारित नहीं हो सके। सत्र 18 मिनट तक चला। सत्र समाप्त होने के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी संसद पहुंचे। फिलहाल संसद के निचले सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामा जारी है। कल इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित होने से पहले विपक्षी दलों ने वाकआउट किया था। पत्रकार संगठनों ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका में पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को हत्या के केस में 16 साल और आठ महीने जेल की सजा

केंट (अमेरिका)। केंट के मालेंग क्षेत्रीय न्याय केंद्र (अदालत) ने गुरुवार को 26 वर्षीय जेसी सारे हत्याकांड पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को दोषी ठहराते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी सारे की 31 मई, 2019 को ऑबर्न बाजार के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा का ऐलान किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश निकोल गेन्स फेल्प्स ने किया। जेफरी नेल्सन को वाशिंगटन में गिरफ्तार किया गया था। इस फैसले से वह ऑन-ड्यूटी हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पुलिसकर्मी बन गए। न्यायाधीश फेल्प्स ने लगभग अधिकतम सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, जेसी सारे को 31 मई, 2019 को ऑबर्न बाजार के बाहर गिरफ्तार करने के दौरान गोली मारी गई थी। अभियोजन ने राज्य की मानक सीमा के तहत सबसे लंबी सजा 18 साल और चार महीने की मांग की थी। अदालत ने जेफरी नेल्सन के चाल-चलन को देखते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जून में एक जूरी ने पूर्व पुलिस अधिकारी 46 वर्षीय नेल्सन को सेकेंड-डिग्री हत्या और फर्स्ट-डिग्री हमले का दोषी ठहराया था। ऑबर्न पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सैम बेट्ज का कहना है कि नेल्सन का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। इसी वजह से हत्या का आरोप लगने के बाद पुलिस भर्ती पोस्टरों पर उनकी छवि का इस्तेमाल किया गया।

खालिदा जिया को लंदन में अस्पताल से बेटे के घर शिफ्ट करने की तैयारी

लंदन। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को अस्पताल से उनके बेटे तारिक रहमान के लंदन स्थित किंग्स्टन निवास पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके निजी चिकित्सक ने कहा कि वयोवृद्ध बेगम खालिदा जिया का इलाज अब तारिक रहमान के घर पर होगा। बेगम खालिदा इस समय द लंदन क्लिनिक में भर्ती हैं। बेगम खालिदा के निजी चिकित्सक और बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य डॉ. एजेडएम जाहिद हुसैन ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 :30 बजे द लंदन क्लिनिक के सामने पत्रकारों से यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया शुक्रवार रात को बेटे के घर जा सकती हैं। घर पर डॉ. पैट्रिक कैनेडी और डॉ. जेनिफर क्रॉस की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा। उन्होंने खालिदा जिया के ठीक होने की प्रार्थना की है। डॉ. जाहिद ने कहा कि अगर उनकी सेहत में सुधार इसी दर से जारी रहा तो वह जल्द ही बांग्लादेश लौट सकती हैं। हालांकि डॉ. जाहिद ने साफ किया कि लीवर प्रत्यारोपण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि खालिदा जिया की उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए लिवर प्रत्यारोपण की संभावना फिलहाल कम है।

तीन छात्राओं की हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद, 52 साल बाद पैरोल पर होगा विचार

लंदन । ब्रिटेन में 3 स्कूली छात्राओं की हत्या के मामले में दोषी करार एक 18 साल के युवक को कठोर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे कम से कम 52 साल की सजा काटनी होगी, तब जाकर उसके पैरोल पर विचार किया जाएगा।अक्सेल रुडाकुबाना (जो हत्या के समय 17 साल का था) ने सात से 13 साल के आठ अन्य बच्चों, योग ट्रेनर लीन लुकास और बिजनेसमैन जॉन हेस की हत्या का प्रयास करने का भी अपराध स्वीकार किया था। लिवरपूल क्राउन कोर्ट में सजा सुनाते हुए जज जूलियन गूज ने कहा कि अगर रुडाकुबाना हमले के समय 18 साल का होता, तो उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती और उसे कभी रिहाई का मौका नहीं मिलता। जज ने कहा, वह अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा हिरासत में बिताएगा। मुझे लगता है कि उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा और वह अपनी पूरी जिंदगी हिरासत में रहेगा। पिछले साल जुलाई में उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाले योग और डांस वर्कशॉप में तीन स्कूली लड़कियों की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया था। उसको गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह अपराध आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

पाक में स्वतंत्र पत्रकारिता करना मुश्किल मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में दावा

लाहौर

पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता की राह और मुश्किल हो गई है। स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर मीडिया आउटलेट्स को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बेमानी हो जाती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने गुरुवार को पिछले दो वर्षों के दौरान देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पत्रकार माहिम माहेर के शोध पर आधारित है। इसमें मीडिया के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे अपवित्र गठबंधनों की भी चर्चा की गई है।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति का विस्तृत विवरण है। रिपोर्ट में मीडिया के कुछ वर्गों पर कड़े प्रतिबंध और दूसरों के लिए उदारता पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंदा निस्संदेह कड़ा हो गया है। एक पत्रकार की हत्या और अन्य को जबरन गायब कर भय पैदा किया गया। सोची-समझी प्रेस सलाह और डिजिटल स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के कानूनी बदलाव मुल्क में स्वतंत्र पत्रकारिता की राह में रोड़ा खड़ कर रहे हैं।

एचआरसीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में सेंसरशिप के बढ़ते खतरे के बीच डिजिटल मीडिया फिलहाल खुलकर लिख रहा है। इस बीच बड़े मीडिया घरानों में भरोसे की कमी का फायदा सत्ता प्रतिष्ठान ने जमकर उठाया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे राष्ट्र की गंभीर तस्वीर पेश करती है जहां कानूनी, संस्थागत और गुप्त दबावों के संयोजन से बोलने की आजादी को खत्म कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक सॉफ्टवेयर अपडेट का बढ़ना है।यह शब्द पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अपहरण, पूछताछ और जबरदस्ती अनुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के परिणामस्वरूप अकसर जबरन स्वीकारोक्ति कराई जाती है। इसका मकसद ईमानदार पत्रकारों को उनकी भूमिकाओं से अलग करना होता है। जोर-जुल्म की वजह से वह अपना काम स्वतंत्र रूप से जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। 2024 के आम चुनाव सही रिपोर्टिंग मीडिया कवरेज पर अभूतपूर्व प्रतिबंधों के कारण बाधित हुई।

एचआरसीपी के अनुसार, पत्रकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि वह इमरान खान या उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का नाम लेने से बचें। न्यूज रूम के एक कर्मचारी ने तीन मिनट की एक संक्षिप्त बैठक के बारे में बताया कि संघीय सरकार के प्रतिनिधियों ने आदेश दिया था कि इमरान खान का नाम ऑन एयर नहीं लिया जाएगा।

इस रिपोर्ट में 2022 में केन्या में एआरवाई के पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इससे समाचार कक्षों में डर व्याप्त हो गया।

पत्रकारों ने बचने के लिए बीच का रास्ता अपना लिया।

रिपोर्ट में पाकिस्तान में सेंसरशिप की विरोधाभासी प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि कई आवाजों को दबा दिया गया। इससे सरकार समर्थक लोग बेलगाम हो गया। सरकार से असहमत लोगों की मुश्किल बढ़ गई। दमनकारी हालात के बीच एचआरसीपी को लग रहा है कि सोशल मीडिया प्रतिरोध के लिए बड़े मंच के रूप में उभर रहा है।

एचआरसीपी ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण आवाजों को दबाने से न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा बल्कि संस्थानों में जनता का भरोसा भी कम होगा। रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

हमास का खात्मा नहीं कर पाया इजरायल, गाजा फिर लड़ाकों के कब्जे में

गाजा

हमास और इजरायल के बीच चली जंग में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोगों का घरौंदा मिट गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि इजरायल हर हाल में गाजा को हमास से मुक्त कराना चाहता था। दोनों तरफ की बर्बादी के बाद भी स्थित वहीं की वहीं हैं और गाजा पर हमास का कब्जा नहीं हटा। सड़कों पर हमास के लड़ाके दिख रहे हैं और इजरायल का हमास को खत्म करने का संकल्प अधूरा रह गया।

इजरायल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने मार्च की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे इस्तीफा दे देंगे क्योंकि सेना 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में विफल रही थी।

उनको भी अपने शेष जीवन में इन अपमानजनक तस्वीरों के साथ जीना होगा।7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी के अवसर पर सैनिकों को भेजे गए एक पत्र में, उन्होंने दावा किया था कि इजरायली सेना ने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है और इसकी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए लड़ाई जारी रखी है।

जबकि इजरायल के अंदर और बाहर के एक्सपर्ट और सैनिक एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि हमास के लड़ाकों को हराना असंभव था, जो अपनी छीनी हुई जमीन के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए पूरे दिल से तैयार थे।

ये चेतावनियां गाजा में नरसंहार के दिनों में सुनाई गईं, लेकिन राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। यूरोपीय काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस (ईसीएफआर) नामक थिंक टैंक के मुताबिक हमास ने करीब 6,000 लड़ाकों को खो दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपने रिजर्व से लगभग 6,000 सदस्यों की भर्ती कर रहे हैं।

गाजा में हमास लड़ाकों की फिर से हर जगह दिख रही मौजूदगी ने इजरायल को झकझोर कर रख दिया है। हमास लड़ाकों की फिर से मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि 470 दिनों की लगातार बमबारी और जमीनी हमले ज्यादातर निरर्थक रहे हैं।

युवाओं की जय-जयकार के बीच हमास के लड़ाकों की फिर से मौजूदगी उन इजरायली नेताओं को लगातार परेशान करती रहेगी, जो इस भ्रम में थे कि वे उन लड़ाकों को खत्म कर सकते हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए कई दशकों से संघर्ष किया है।

हमास लड़ाकों की फिर से मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि फिलिस्तीनी कभी भी आजादी और न्याय के अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे।

ग्लास पिरामिड प्रवेश स्थल के पास से निकलते हुए पर्यटक

पेरिस में म्यूजियम के ग्लास पिरामिड प्रवेश स्थल के पास से निकलते हुए पर्यटक।

ट्रंप ने बताया यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोकने का फॉर्मूला कहा- कम करें तेल की कीमतें

वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के दूसरे देशों से तेल की कीमतें कम करने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें कम होने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तत्काल खत्म करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्विटरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान ये बात कही है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए चेतावनी दी थी।

दावोस में बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सऊदी अरब और ओपेक से भी तेल की कीमत करने के लिए कहने जा रहा हूं। आपको इसे कम करना ही होगा। सच कहूं तो मुझे

आश्चर्य है कि उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा न करके उन्होंने बहुत प्यार नहीं दिखाया। मैं इससे थोड़ा हैरान हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए ओपेक देशों को एक हद तक जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमत कम हो जाती है तो रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तेल की कीमत इतनी अधिक है कि युद्ध जारी रहेगा। आपको तेल की कीमत करनी होगी। आपको युद्ध समाप्त करना होगा। उन्हें यह बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वे एक हद तक जिम्मेदार हैं। रिपब्लिकन नेता ने तेल की कीमतों के साथ ही ब्याज दरों को भी तुरंत कम करने की मांग की।

लंदन में कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर बवाल, स्क्रीनिंग रुकी, ब्रिटेन की संसद में गूंज

लंदन

कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि ब्रिटेन में भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के प्रदर्शन पर बाधा डालने वाले आतंकवादी हैं। उन्होंने गृह सचिव यवेटे कूपर से दखल देने का आग्रह किया है। ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटेन की संसद के निचले सदन) में कहा कि दर्शकों को शांति और सद्भाव के साथ फिल्म देखने के लिए कारगर उपाय किए जाएं।

रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए यह जानकारी दी। द हेराल्ड की खबर के अनुसार, हैरो ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि व्यू सिनेमा श्रृंखला के हैरो स्थित सिनेमा हाल में विवादास्पद बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वाले नकाबपोश प्रदर्शनकारी आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रविवार को टिकट खरीदकर हैरो व्यू सिनेमा में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग को देखने गए। करीब 30 से 40 मिनट बाद नकाबपोश खालिस्तानी आतंकवादी घुस आए। नकाबपोशों ने दर्शकों को धमकी दी और फिल्म का प्रदर्शन रोक देने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही वॉल्वरहैम्प्टन, बर्मिंघम, स्लो, स्टेंस और मैनचेस्टर में हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि व्यू सिनेमाज और सिने वर्ल्ड ने इस फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया है। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि वह फिल्म की गुणवत्ता या सामग्री पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिल्म देखना दर्शकों का अधिकार है। उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के दर्शकों को फिल्म देखने में दिक्कत न हो, इसके तत्काल उपाय किए जाएं। हाउस ऑफ कॉमन्स नेता लुसी पॉवेल ने कहा, बॉब ब्लैकमैन ने महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें और पूरे सदन को यह जानकारी मिले कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। इस पर ब्लैकमैन ने सवाल किया कि क्या अगले हफ्ते गृह सचिव का बयान आ सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स में मुद्दा उठने के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि सिनेमा हाल में घुसे लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इमरजेंसी फिल्म 1975 से 1977 के मध्य के भारतीय कालखंड पर केंद्रित है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई।